Fourteenth Loksabha

Session : 9
Date : 19-12-2006

Participants : Suman Shri Ramji Lal

>

Title: Need to implement the recommendations of Committee set up by Ministry of Human Resource Development before giving permission to foreign universities to operate in the country.

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : महोदय, शिक्षा क्षेत्र में उदारीकरण का लाभ लेने और उसे व्यापक बनाने हेतु सरकार ने ि वदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश व उनके विभिन्न पाठयक्रमों के संचालन हेतु सैद्धांतिक रूप से सहमति जताई हैं परंतु सरकार इन ि वदेशी विश्वविद्यालयों के संचालन हेतु नियामक तंत्र अभी तक नहीं बना पायी है जबकि देश में पहले से ही 144 विदेशी विश्वि वद्यालय, महाविद्यालय और संस्थान चल रहे हैं, जिसमें 117 अपने अपने देश के पाठयक्रमों का संचालन कर रहे हैं। सरकार की इस उदारीकरण नीति पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थायी समिति ने रिपोर्ट दी है कि विदेशी विद्यालयों और संस्थानों की पृठभूमि, उनकी मान्यताओं तथा क्षमताओं की जांच पड़ताल हेतु सरकार एक समिति गठित करे और विदेशी संस्था अगर झूठी पायी जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इंडियन काउंसिल ऑफ टैक्नीकल एजूकेशन के दायरे में सिर्फ वही विदेशी विश्वि वद्यालय आते हैं जो तकनीकी शिक्षा हेतु भारतीय विश्वविद्यालयों के साथ समझौता किए हुए हैं।

उक्त समिति के सुझावों को अगर सरकार नजरअंदाज करती है तो देश के लाखों लोगों को सस्ती सुलभ शिक्षा नसीब नहीं हो सकती है। भारत में जहां गरीबी के कारण, सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद लाखों घरों के बच्चे अभी भी स्कूल जाने से महरूम रह जाते हैं वहीं विदेशी और महंगी शिक्षा क्या गरीब परिवारों के बच्चों को सरकार मुहैया करा पाएगी? सरकार के इस कदम के कारण शिक्षा क्षेत्र में और स्पर्धा आने की ही संभावना है।

मेरा सरकार से आग्रह है कि वे विदेशी विश्वविद्यालय के प्रवेश से पहले उसके हर पहलू पर बड़ी संजीदगी से विचार कर भारतीय कानून के दायरे में तथा समिति के सुझावों के अनुरूप ही उन्हें भारतीय सरजमीं पर आने की इजाजत दें।